बेतुकी बयानबाजी से बचें

गठबंधन सरकार की अगुआई कर रही शिवसेना की तरफ से भी उसके प्रवक्ता संजय राउत ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिन्हें गठबंधन धर्म के अनुरूप मानना मुश्किल हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि पारंपरिक तौर पर शिवसेना की सोच बीजेपी के करीब रही है।

सुंदर सिंह।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने ताजा बयान से उपजे विवाद को शांत करने के लिए वही रास्ता अपनाया जो लापरवाही भरे बयान जारी करने वाले नेता अक्सर अपनाते हैं। उन्होंने पूरा दोष मीडिया के मत्थे मढ़ते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़–मरोड़ कर दिखाया गया और दरअसल उनका इशारा प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ओर था। बहरहाल, यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान ने पार्टी और राज्य सरकार को असहज किया है। वे न केवल बार–बार कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं बल्कि सरकार पर परोक्ष रूप से घोटाले का भी आरोप लगा चुके हैं। चुनाव लड़ने की घोषणाओं का तो वे बचाव भी करते रहे हैं। यह सही है कि तीन विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों का यह गठबंधन स्थायी नहीं है। लेकिन प्रदेश में कार्यकाल पूरा करने वाली एक स्थिर सरकार देना तो इस गठबंधन का घोषित मकसद रहा है। राज्य में अगला विधानसभा चुनाव 2024 में होना है। अभी मौजूदा सरकार ने आधा कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। फिर भी उसकी तैयारी करना, पार्टी संगठन को सचेत रखना किसी पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या इसकी बार–बार सार्वजनिक घोषणा करना भी उतना ही जरूरी है?

इरादा हो या न हो, इससे यह संदेश जाता है कि प्रदेश की गठबंधन सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं दुविधा और असमंजस में है। मगर ऐसा संकेत देने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। गठबंधन सरकार की अगुआई कर रही शिवसेना की तरफ से भी उसके प्रवक्ता संजय राउत ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिन्हें गठबंधन धर्म के अनुरूप मानना मुश्किल हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि पारंपरिक तौर पर शिवसेना की सोच बीजेपी के करीब रही है। लेकिन इसके बावजूद दोनों इस बार साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकीं और शिवसेना ने अपनी राह अलग करते हुए एनसीपी तथा कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का अपेक्षाकृत कठिन रास्ता चुना। अब जब यह कांटों भरी राह चुन ली तो इस पर आगे बढ़ने के बजाय बीच–बीच में पुराने रास्ते को याद करके बिसूरते रहना मौजूदा सफर को और कठिन बनाएगा। गठबंधन में शामिल सभी पक्षों को यह याद रखना चाहिए कि फिलहाल उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य को एक स्थिर और अच्छा शासन मुहैया कराने की है जिसका कि तीनों दलों ने अपने वोटरों से वादा भी किया है। एक बार सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले तो चुनाव वे जैसे चाहें लड़ें, लेकिन उससे पहले गठबंधन के तकाजों को समझना और उसका पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्वाह करना तीनों दलों का लोकतांत्रिक दायित्व भी है। बेहतर होगा कि तीनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इसे लेकर थोड़ी और सावधानी बरते।

कठिन परिश्रम

अशोक वोहरा।

विष्णु बोले– लौट आए नारद! ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद बोले – एक बार भी नहीं भगवान ! करता भी कैसे मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था।

श्रीहरि बोले – तब तुम्हीं सोचो। वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है। फिर भी दो–चार बार मेरा स्मरण जरूर करता है और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए।

विष्णु की बात सुनकर नारद के अन्तर्चक्षु खुल गए। वह श्रीहरि के चरणों में गिरकर बोले – मान गया प्रभु! जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा – नारद जी! नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो।

संपादकीय

कर्ज की महामारी

एवरग्रैंड मामले से सबक लेकर भारत में अभी इतना ही किया जा सकता है कि डिफॉल्ट के कगार पर बैठी कंपनियों का हिसाब–किताब रखा जाए और उन्हें बचाने के लिए समय रहते जरूरी उपाय किए जाएं। जिन कंपनियों का पुराना कर्जा संदिग्ध स्थिति में हो उन्हें बचाने के लिए नया कर्जा बांटने के बजाय उनके कारोबार की दशा सुधारने के लिए काम किया जाए। कोरोना की बीमारी अभी गई नहीं है। रूस के केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों अपनी मुख्य ब्याज दर एक ही बार में सीधे एक फीसदी बढ़ा दी। बाकी देश इस दिशा में कब कदम बढ़ाते हैं, यह देखने की बात है। ऐसा जब भी होगा, कोरोना के दौरान रचे गए कई सारे तिलस्म टूट जाएंगे। यह एक विडंबना ही है कि इस तरह का पहला झटका हमें चीन में दिखा है, जहां कोरोना का प्रकोप सबसे पहले आया था, लेकिन जिसका असर उसी को सबसे कम झेलना पड़ा। बताया जा रहा है कि एवरग्रैंड की समस्याओं की शुरुआत चीनी केंद्रीय बैंक द्वारा पिछले साल जारी की गई 'थ्री रेड लाइंस' के साथ हुई थी। लिहाजा सरकारों के सामने पहली प्राथमिकता बीमारी से निपटने और लोगों का रोजगार बचाए रखने की ही है। लेकिन ग्लोबल अर्थव्यवस्था बड़ी बेरहमी से काम करती है और बड़े–बड़े महल इसमें ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लिहाजा एक आंख हमें कर्जे से जुड़ी वित्तीय महामारी पर भी रखनी होगी।

चीन दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी। लेकिन चीन में ठंड बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को जुकाम लग जाए, ऐसी नौबत तो अभी नहीं आई है।

महंगाई का प्रकोप

चंद्रभूषण।।

चीनी रीयल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड की क्रेडिट रेटिंग पिछले दो महीनों में एक ही इंटरनैशनल रेटिंग एजेंसी द्वारा तीन बार डाउनग्रेड की गई, लेकिन हाल–हाल तक वह किसी बड़ी समस्या से इनकार करती रही। फिर अचानक कंपनी ने बयान जारी किया कि उसके बनाए मकानों, दुकानों और दफ्तरों की नई सेल लगभग पूरी तरह रुक गई है और कर्जों की किस्तें लौटाने में उसको समस्या हो सकती है। एवरग्रैंड का डिफॉल्ट करना कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप उसके कर्जों पर नजर डालें। उसने कई चीनी बैंकों से कुल मिलाकर 300 अरब डॉलर का कर्जा ले रखा है। भारतीय रुपयों में यह रकम 22 लाख करोड़ रुपये से जरा ज्यादा ही बैठती है!

निश्चय ही यह राशि काफी बड़ी है, लेकिन अगर यह पूरी तरह डूब जाए तो भी हमारे लिए इसमें चिंता की क्या बात है? चीन दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी। लेकिन चीन में ठंड बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को जुकाम लग जाए, ऐसी नौबत तो अभी नहीं आई है। चीनी केंद्रीय बैंक ने एवरग्रैंड मामले में रुचि लेनी शुरू कर दी है और बिल्कुल संभव है कि अगले कुछ दिनों में वह इस कंपनी को कर्जा देने वाले

बैंकों को देर से अदायगी और हेयरकट (ब्याज, मूलधन या दोनों में कटौती) के लिए राजी कर ले। उसकी असल चिंता यह है कि इस कंपनी की बीमारी कहीं पूरे रीयल एस्टेट सेक्टर में न फैल जाए, जिसने फिलहाल चीन के कुल जीडीपी के एक चौथाई के बराबर कर्जा उठा रखा है। यहां से आगे समस्या दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में और चीनी अर्थव्यवस्था से बाहर भी जा सकती है।

पिछले हफ्ते रूस के केंद्रीय बैंक ने दुनिया में सरकारी और निजी कर्जे 25 ट्रिलियन डॉलर– अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सवा गुना– की सीमा पार कर जाने की बात कही थी। इस कर्जे के बोझ को लेकर तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी हर जगह सस्ती से सस्ती दर पर ज्यादा से ज्यादा कर्जा बांटने, पिछले कर्जे की उगाही टालने और जितना हो सके उतना माफ कर देने की उम्मीद सरकारों से की जा रही है। ऐसा माहौल न रहता तो अब से छह–सात साल पहले जिस तरह ग्रीस का दिवाला पिटा था और दक्षिणी यूरोप के कई देशों के कर्जे की बाढ़ में डूब जाने की बातें हवा में थीं, वैसी कई घटनाएं पिछले डेढ़ वर्षों में ही हो चुकी होतीं। छोटे–मोटे कई देशों के केंद्रीय बैंक कर्ज अदायगी में असमर्थता जताकर अलग ही तरह का मानवीय संकट पैदा कर चुके होते।

फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह न लगाया जाए कि बीमारी से जुड़ी सुस्ती को छोड़कर बाकी सब ठीक–ठाक है। बेहिसाब बांटे गए कर्जे का असर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही महंगाई की शक्ल में दिखाई पड़ने लगा है। शास्त्रीय हिसाब से इसकी वजहें तीन हैं। एक यह कि कुछ चीजों का उत्पादन अभी पूरी क्षमता पर नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी मांग अपने स्वाभाविक स्तर पर आ गई है– सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। बेरोजगारी नियंत्रित रखने के लिए सरकारों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बहुत बढ़ा दिया है। लिहाजा सीमेंट, लोहा और निर्माण कार्य से जुड़े बाकी सामानों में मांग आधारित महंगाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार में मुद्रा की आपूर्ति चीजों और सेवाओं की खरीद–बिक्री से जुड़ी जरूरतों से कहीं ज्यादा हो जाने के कारण पैदा होने वाली तीसरी तरह की महंगाई रहस्यमय ढंग से बढ़ती है और अपने पीछे भ्रष्टाचार और विषमता का परनाला छोड़ती हुई आती है।

सूडोकु नवताल- 5294

सरल

			2				3	
		9		8		2	6	4
1				3	6		9	
4		3						
	8			2			1	
						8		6
	4		7	5				3
3	7	5		4		1		
	2				8			

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5293 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

भारत के मुसलमान और ईसाई देशभक्त

मोहन। असली प्रश्न यह है कि यदि भारत मुस्लिम बहुसंख्यक देश होता तो क्या यहां वे सब स्वतंत्रताएं होतीं जो आज हैं ? उन्होंने साथ–साथ यह भी कह दिया कि भारत के मुसलमान और ईसाई देशभक्त हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका यह कथन बिल्कुल सही है। मुस्लिम देशों के बारे में उन्होंने जो कहा है, वह बहुत हद तक सही है लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। इसमें शक नहीं कि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में आज हजार–डेढ़ हजार साल पुराने अरबी कानून इस्लाम के नाम पर चल रहे हैं। जो क्रांतिकारी आधुनिकता पैगंबर मोहम्मद खुद लाए थे, गएकृबीते अरबी कानूनों और परंपराओं में, उस आधुनिकता की प्रवृत्ति पर आज भी कई इस्लामी देश आँख मूंदे हुए हैं लेकिन मैंने स्वयं अफगानिस्तान, ईरान, दुबई, ईराक और लेबनान जैसे देशों में अब से 50–55 साल पहले अपनी आंखों से देखा है कि उन देशों में कई लोगों की जीवन–पद्धति भारतीय भद्रलोक से भी ज्यादा आधुनिक थी।